the same site after demolising he old one. There is no other proposal for construction of such hostels during the current year.

निजी क्षेत्र को आवासीय भूमि का आबंटन

4289. **श्री राम जेठमलानी** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 दिसम्बर, 1991 के "फाइनैंसियल एक्सप्रेस" में प्रकाशित "गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लैण्ड टु प्राइवेट डेवलपर्स इन दिल्ली" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है, यदि हां, तो क्या प्रस्तावित राष्ट्रीय आवास नीति के अधीन यह उपबंध किया गया है कि दिल्ली में आवासीय भवनों के निर्माण के लिये निजी क्षेत्र को भूमि आबंटित की जाये ;

(ख) यदि ऊपर भाग (क) का उत्तर "हां" हो, तो इस नीति में सामूहिक आवास समितियों को प्राथमिकता न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि यदि सहकारी समितियों को निजी क्षेत्र की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है तो आम आदमी को अधिक लाभ प्राप्त होगा और उसके शोषण की संभावना भी नहीं होगी, यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में सहकारी क्षेत्र को प्राथमिकता देगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (ख) जी, हां । किन्तु यह कहना सही नहीं है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय आवास नीति दिल्ली में रिहायशी मकानों के निर्माण के लिए सामूहिक आवास समितियों की लागत पर निजी क्षेत्र को भूमि आबंटन की व्यवस्था करती है ।

(ग) सरकार आवास के क्षेत्र में सहकारीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए वचनबद्ध है ।

Forcible occupation of property of a Destitute widow by MCD

4290. SHRIMATI PRATIBHA SINGH:
SHRI ASHOK NATH VERMA:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 812 given in the Rajya Sabha on 6th September, 1991 and state:

(a) whether it is a fact that destitute widow's portion is 1/4th of the building in question where MCD is running a firls primary school, if so, what are the details thereof;

(b) whether it is also a fact that just opposite this school, another girls primary school is functioning, which is MCD owned building and which is partly lying vacant and unutilised and only one shift is functioning if so, what are the details thereof, serialwise;

(c) whether Government would examine the possibility to get vacated the 1/4th portion of the widow's building which is long back disputed and debated at several forms, and ordered and assured to be vacated but not yet complied with if so, what are the details thereof; and

(d) whether Government would allot alternative plot site, some where else to the destitute widow in case such premises could not be vacated so as to end gross injustice?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.